शनिवार

01 अगस्त 2026

- देहरादून
- वर्ष 34
- अंक 189
- पृष्ठ 8
- मूल्य ₹ 1.00

34 साल से देहरादून का विश्वास

दून वैली मेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94

email: doonvalley_news@yahoo.com Website: dunvalleymail.com

डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

दहेज हत्या प्रकरण: पति व ननद गिरफ्तार

हमारे संवाददाता

देहरादून। दहेज हत्या मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस ने हत्यारोपी पति व ननद को गिरफ्तार कर लिया है। जिन्हे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि बीती 29 जुलाई को सीमा कण्डारी पत्नी स्व. सुमेर सिंह कण्डारी निवासी श्रीकोट, निकट गेस गोदाम श्रीनगर जिला पौडी गढवाल द्वारा कोतवाली डोईवाला पर तहरीर देकर बताया गया था कि उन्होने पुत्री सृष्टि कण्डारी का विवाह नवम्बर 2025 में सौरभ खत्री निवासी लक्ष्मण एन्कलेव, दिल्ली फार्म, हर्रावाला, देहरादून के साथ किया था। विवाह के बाद से ही उसके ससुराल पक्ष द्वारा उनकी पुत्री को दहेज के लिए प्रताडित करने तथा उनकी पुत्री के ससुराल पक्ष (पति सौरभ खत्री, सास परवीना देवी व ननद चारू) द्वारा उनकी पुत्री की हत्या की गयी है।

मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी। जांच के दौरान पुलिस टीम को मृतका की मां द्वारा घटना से पूर्व मृतका द्वारा उन्हें भेजी गयी एक वीडियो उपलब्ध कराई गयी, जिसमें मृतका द्वारा शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा उसे लगातार प्रताडित किये जाने की बात बताई गयी थी।

पुलिस द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही व प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आज सुबह पुलिस टीम द्वारा घटना में नामजद दो आरोपियों सौरभ खत्री पुत्र स्व. मनोहर खत्री तथा सुरभि खत्री उर्फ चारू पुत्री स्व. मनोहर खत्री निवासी लक्ष्मण एन्केलव दिल्ली फार्म हर्रावाला कोतावाली डोईवाला देहरादून को लक्ष्मण एन्क्लेव, दिल्ली फार्म, हर्रावाला से गिरफ्तार किया गया है।

मुस्लिम समुदाय से जुडी पुरानी संरचना पर कार्रवाई से बवाल, जाम लगाया

संवाददाता

देहरादून। मसूरी के लक्ष्मण पुरी में मुस्लिम समुदाय की पुरानी संरचना पर प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने आक्रोश जताते हुए जाम लगाकर कार्यवाही का विरोध किया। समाचार लिखे जाने तक विरोध प्रदर्शन जारी था।

आज यहां जिला प्रशासन की टीम मसूरी स्थित लक्ष्मण पुरी में स्थित एक मुस्लिम समुदाय की संरचना को ध्वस्त करने के लिए पहुंची। जिला प्रशासन की टीम के पहुंचते ही वहां काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हो गये और प्रशासन की कार्यवाही का विरोध करने लगे।

उन्होंने जिला प्रशासन को उक्त स्थान के दस्तावेज व अंग्रेजों के समय 1914 का नक्शा दिखाया। रजिस्ट्री के कागजात भी जिला प्रशासन की टीम को दिखाये। उनका कहना था प्रशासन यहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स लेकर आये हैं जिससे यहां का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना था कि यह प्रशासन व सरकार का तानाशाही रवैया है। पहले प्रशासन ने कहा कि मस्जिद की मीनार हटा दो तो उनके द्वारा स्वंय मीनार तोड दी गयी। उनका कहना था कि यह कब्रिस्तान 1914 से है तथा यहां पर उनके बुजुर्ग लोगों की कब्र है। उनका कहना था कि यह 200 साल पुराना कब्रिस्तान है जिसमें उनके द्वारा बारिश से बचने के लिए एक कमरे का निर्माण किया गया है। प्रशासन के रवैये को देखते हुए लोगों ने वहां जाम लगा दिया। समाचार लिखे जाने तक बवाल जारी था।

दून वैली मेल

संपादकीय

तोहफों की राजनीति या निवेश

लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार का हर बड़ा फैसला अब केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं रह जाता, बल्कि उसके राजनीतिक संदेश भी तलाशे जाते हैं। ऐसे समय में मोदी कैबिनेट द्वारा किसानों और युवाओं को केंद्र में रखकर लिए गए हालिया फैसलों ने यह संकेत देने की कोशिश की है कि सरकार 2029 की राह में ग्रामीण भारत, कृषि और युवा वर्ग को अपनी प्राथमिकता बनाए रखना चाहती है। कैबिनेट ने पीएम-किसान सम्मान निधि योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाते हुए लगभग 3.15 लाख करोड़ से अधिक के प्रावधान को मंजूरी दी है। इसके साथ ही खेलों को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित खेलो इंडिया कार्यक्रम और पीएम सूर्य सरोवर योजना जैसे फैसलों को भी हरी झंडी दी गई है। सरकार का तर्क है कि इन निर्णयों से किसानों की आय, युवाओं के अवसर और हरित विकास को नई गति मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ योजनाओं का विस्तार ही पर्याप्त है? पीएम-किसान योजना ने करोड़ों किसानों तक प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया है। इससे छोटे किसानों को खेती के लिए नकदी उपलब्ध होती है और साहूकारों पर निर्भरता कुछ हद तक घटती है। यह भी सच है कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ने पारदर्शिता बढ़ाई है। लेकिन आज भारतीय किसान की सबसे बड़ी चुनौती केवल नकद सहायता नहीं, बल्कि खेती की बढ़ती लागत, मौसम की अनिश्चितता, सिंचाई, बाजार और उचित मूल्य भी हैं। यदि छह हजार रुपये सालाना सहायता मिल भी जाए, लेकिन उर्वरक, डीजल, बीज और मजदूरी की लागत लगातार बढ़ती रहे, तो यह राहत सीमित साबित होती है। इसलिए सरकार की अगली चुनौती कृषि को केवल सहायता आधारित नहीं, बल्कि लाभकारी व्यवसाय बनाने की होनी चाहिए। युवाओं के संदर्भ में भी यही स्थिति है। खेलो इंडिया का विस्तार और खेल अवसंरचना पर निवेश स्वागतयोग्य है। इससे प्रतिभाओं को मंच मिलेगा और भारत की खेल शक्ति मजबूत होगी। लेकिन देश के करोड़ों युवाओं की सबसे बड़ी चिंता आज भी रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया है। सरकार ने हाल के महीनों में परीक्षा प्रणाली में सुधार और भर्ती प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। इसके बावजूद युवाओं का विश्वास तभी मजबूत होगा, जब सरकारी भर्तियां समय पर पूरी हों, प्रतियोगी परीक्षाएं विवादों से मुक्त रहें और निजी क्षेत्र में भी रोजगार सृजन तेजी से बढ़े। इन फैसलों का समय भी महत्वपूर्ण है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव, मानसून पर निर्भर कृषि, युवाओं की अपेक्षाएं और विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनावकृइन सबके बीच सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसका फोकस किसान और युवा दोनों हैं। विपक्ष इसे चुनावी तैयारी कह सकता है, जबकि सरकार इसे विकास की निरंतरता बताएगी। दोनों दावों के बीच अंतिम फैसला जनता करेगी। सरकार की नीतियों का मूल्यांकन केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि उनके जमीनी असर से होना चाहिए। यदि पीएम-किसान का पैसा समय पर किसानों तक पहुंचे, खेल योजनाओं से गांवों के खिलाड़ी राष्ट्रीय मंच तक पहुंचें और युवाओं को रोजगार एवं निष्पक्ष अवसर मिलें, तब यह फैसले केवल राजनीतिक घोषणा नहीं बल्कि दूरगामी निवेश साबित होंगे। भारत आज उस दौर में है जहां कल्याणकारी योजनाओं और आर्थिक सुधारों के बीच संतुलन सबसे बड़ी चुनौती है। किसानों को सम्मान, युवाओं को अवसर और अर्थव्यवस्था को गति यदि ये तीनों लक्ष्य साथ-साथ आगे बढ़ते हैं, तभी ऐसे फैसले इतिहास में सफल माने जाएंगे। अंततः किसी भी सरकार की असली सफलता योजनाओं की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि वह आम नागरिक के जीवन में कितना वास्तविक परिवर्तन ला पाती हैं। किसानों और युवाओं को दिया गया यह तोहफा तभी सार्थक होगा, जब यह चुनावी सुर्खियों से निकलकर खेतों, गांवों, खेल मैदानों और रोजगार के अवसरों तक पहुंचे। यही इसकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी।

देहरादून साइक्लिंग क्लब ने शुरू किया देहरादून के गड्ढों से आजादी जन अभियान

संवाददाता

देहरादून। देहरादून साइक्लिंग क्लब ने देहरादून के गड्ढों से आजादी जन अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान आजादी का अमृत महोत्सव की भावना को समर्पित है, जिसका उद्देश्य नागरिकों की सहभागिता से देहरादून को गड्ढा मुक्त बनाने की दिशा में एक जन आंदोलन खड़ा करना है। इस अभियान के अंतर्गत नागरिकों से अपील की गई है कि यदि उनके आसपास कोई टूटी हुई सड़क, बड़ा गड्ढा अथवा क्षतिग्रस्त मार्ग है तो वे जीपीएस कैमरे से से उसकी फोटो लें। फोटो में स्थान (लोकेशन) स्पष्ट दिखाई दे। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर @Dehradun Cycling Club को टैग करें। अथवा वट्सअप 8755960120 पर भेजें। देहरादून साइक्लिंग क्लब के अध्यक्ष हरिसिमरन सिंह ने कहा कि यह केवल एक शिकायत अभियान नहीं, बल्कि नागरिकों की भागीदारी से शहर को सुरक्षित और बेहतर बनाने का प्रयास है। उन्होंने कहा,देहरादून को गड्ढों से आजाद कराना हमारा संकल्प है। जब तक शहर की हर प्रमुख सड़क सुरक्षित और गड्ढामुक्त नहीं हो जाती, तब तक हमारा अभियान निरंतर जारी रहेगा। यही आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का सबसे सार्थक तरीका है, जब हम अपने शहर को सुरक्षित, सुगम और बेहतर बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करें।

जनगणना में भी पहाड़ 'अदृश्य'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड को अक्सर देवभूमि कहा जाता है। चुनाव आते हैं तो वीरभूमि भी कहा जाता है। पर्यटन की बात होती है तो स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन जब सरकारी फाइलों में गिनती होती है, तब यही उत्तराखंड अक्सर सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाता है। संसद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड के लिए विशेष पर्वतीय जनगणना माडल की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि अपनी गणना, अपना गांव की तर्ज पर ऐसी जनगणना होनी चाहिए, जो पहाड़ की वास्तविक आबादी, पलायन और गांवों की सच्चाई को दर्ज करे। सवाल यह नहीं है कि यह मांग किसने उठाई। सवाल यह है कि क्या भारत की मौजूदा जनगणना व्यवस्था वास्तव में पहाड़ को देख भी रही है?

उत्तराखंड में हजारों गांव ऐसे हैं जहां मकान खड़े हैं, लेकिन लोग नहीं। दरवाजों पर ताले हैं, खेतों में झाड़ियां हैं और स्कूलों में बच्चों की संख्या हर साल घट रही है। लेकिन जब जनगणना होती है तो वह पूछती है आप अभी कहां रहते हैं? वह यह नहीं पूछती कि आपका गांव कौन-सा है? वह यह नहीं पूछती कि आप हर त्योहार पर किस गांव लौटते हैं? वह यह भी नहीं पूछती कि यदि गांव में रोजगार मिल जाए तो क्या आप वापस लौटेंगे?यही वह खाली जगह है, जिसकी ओर संसद में इशारा किया गया।

उत्तराखंड का पलायन कोई नई खबर नहीं है। इस पर आयोग बने, रिपोर्टें आईं, समितियां बनीं और घोषणाएं हुईं। लेकिन गांव आज भी खाली हैं। सरकारें कहती हैं कि सड़क बना दी। लोग पूछते हैं रोजगार कहां है? सरकार कहती है इंटरनेट पहुंच गया। लोग पूछते हैं युवा वापस क्यों नहीं लौटे? सरकार कहती है पर्यटन बढ़ा। लोग पूछते हैं स्थायी आजीविका कितनों को मिली? यही वजह है कि आज जनगणना केवल जनसंख्या गिनने का विषय नहीं रह गया है। यह विकास माडल की परीक्षा बन गया है। यह बात भी स्वीकार करनी होगी कि यह मांग ऐसे समय आई है जब

◆अपनी गणना, अपना गांव, संसद में महेंद्र भट्ट ने उठाई पर्वतीय जनगणना की मांग
◆बड़ा सवाल, क्या मैदानी पैमानों में सिमट कर रह गई है पहाड़ की आबादी
◆पलायन वरवाली होते गांवों की सच्चाई, आंकड़ों में लौटेंगे खाली होते गांव

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव दूर नहीं हैं। भाजपा जानती है कि पलायन, सीमांत गांव, खाली होते घर और पहाड़ की उपेक्षा ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हर सरकार से सवाल पूछे जाते रहे हैं। इसलिए यदि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष संसद में यह कहता है कि उत्तराखंड के लिए अलग पर्वतीय जनगणना माडल होना चाहिए, तो यह केवल प्रशासनिक सुझाव नहीं है। यह एक राजनीतिक संदेश भी है कि पार्टी पहाड़ की पहचान और उसकी विशेष परिस्थितियों को राष्ट्रीय बहस में लाना चाहती है। लेकिन राजनीति का दूसरा पक्ष भी है।

महेंद्र भट्ट जिस दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसी दल की सरकार राज्य में भी है और केंद्र में भी। इसलिए विपक्ष पूछेगा यदि आज की जनगणना व्यवस्था पहाड़ के साथ न्याय नहीं कर रही थी तो पिछले वर्षों में इसे बदलने की पहल क्यों नहीं हुई? यदि पलायन सबसे बड़ी चुनौती है तो खाली गांवों को आबाद करने की नीतियों का परिणाम क्या निकला? यदि सीमांत गांव रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं तो वहां स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की स्थिति अब भी कमजोर क्यों है? लोकतंत्र में यही स्वाभाविक है। जो सवाल विपक्ष से पूछे जाते हैं, वही सवाल सत्ता से भी पूछे जाएंगे।

यह बात शायद कम लोग जानते हैं कि जनगणना केवल लोगों की गिनती नहीं करती। उसी के आधार पर योजनाएं बनती हैं, संसाधनों का वितरण होता है, स्कूल, अस्पताल, सड़कें और कई सरकारी सुविधाओं की प्राथमिकताएं तय होती हैं। यदि किसी गांव की आबादी कागज पर कम दिखाई देती है तो वहां विकास योजनाएं भी सीमित हो सकती हैं। यदि बाहर रहने वाले लोग पूरी तरह शहरों की आबादी में दर्ज हो जाते हैं, तो पहाड़ की वास्तविक सामाजिक संरचना सरकारी नजर से ओझल हो सकती है। यही कारण है कि विशेषज्ञ लंबे समय से पर्वतीय राज्यों के लिए अलग दृष्टिकोण की बात करते रहे हैं।

यदि इस अवधारणा पर गंभीरता से काम होता है और प्रत्येक नागरिक का अपने मूल गांव से संबंध भी दर्ज किया जाता है, तो सरकार के पास पहली बार यह स्पष्ट तस्वीर होगी कि कितने लोग

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

'वोटर लिस्ट' पर उत्तराखंड में 'संग्राम'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया अब राजनीतिक विवाद का नया केंद्र बन गई है। कांग्रेस ने इस पूरी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और खामियों का आरोप लगाते हुए राज्यभर में मोर्चा खोल दिया है। पार्टी का दावा है कि यदि समय रहते कमियां दूर नहीं की गईं तो हजारों वास्तविक मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। वहीं सत्तारूढ़ भाजपा इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कह रही है कि चुनाव आयोग पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और निर्धारित नियमों के अनुसार संचालित कर रहा है। चुनावी वर्ष से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण हमेशा महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इस बार यह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गई है। यह राजनीतिक संघर्ष का नया अखाड़ा बनती दिखाई दे रही है।

प्रदेश कांग्रेस का आरोप है कि एसआईआर के दौरान कई स्थानों पर मतदाताओं के नाम बिना पर्याप्त सूचना के हटाए जा रहे हैं, नए मतदाताओं के पंजीकरण में अनावश्यक देरी हो रही है और बूथ स्तर पर पर्याप्त सत्यापन नहीं किया जा रहा। पार्टी नेताओं का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग रोजगार के कारण अस्थायी रूप से बाहर रहते हैं। ऐसे परिवारों के नाम हटने का खतरा बढ़ गया है। कांग्रेस का कहना है कि यदि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से बाहर हो गया तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मताधिकार कमजोर होगी। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी जिला मुख्यालयों से लेकर राज्य स्तर तक ज्ञापन, धरना और विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है।

भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को चुनाव से पहले भ्रम फैलाने की रणनीति बताया

◆हजारों नागरिकों के वोट पर मंडराया संकट या सिर्फ जुबानी जंग
◆मतदाता सूची की खामियों को मुद्दा बनाकर कांग्रेस का हल्ला बोल
◆उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के रण से पहले बढ़ी राजनीतिक तपिश

है। पार्टी नेताओं का कहना है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरी तरह चुनाव आयोग की संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसमें राजनीतिक दलों के बूथ एजेंटों को भी आपत्तियां और सुझाव देने का अवसर मिलता है। भाजपा का तर्क है कि यदि किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो उसके लिए निर्धारित अपील और दावा-आपत्ति की व्यवस्था पहले से मौजूद है। ऐसे में कांग्रेस का विरोध केवल राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश है।

इस पूरे विवाद के केंद्र में चुनाव आयोग है। आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध और अद्यतन बनाना है ताकि मृत, स्थानांतरित या दोहरे नामों को हटाया जा सके और नए पात्र मतदाताओं को जोड़ा जा सके। हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल सूची की शुद्धता ही नहीं, बल्कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम सुरक्षित रखना भी उतना ही आवश्यक है। यही कारण है कि आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सभी दलों की निगाहें टिकी हुई हैं। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया मैदानी राज्यों से कहीं अधिक जटिल है। बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और व्यवसाय के लिए दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई या अन्य शहरों में रहते हैं, जबकि उनका स्थायी निवास गांवों में है। कई गांवों में पलायन के कारण परिवार वर्ष के अधिकांश समय बाहर रहते हैं। यदि ऐसे मामलों में पर्याप्त सत्यापन के बिना नाम हटाए जाते हैं तो विवाद स्वाभाविक रूप से बढ़ सकता है। यही मुद्दा कांग्रेस जोर-शोर से उठा रही है।

इस बार पहली बार मतदान करने वाले युवाओं का पंजीकरण भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। कांग्रेस का आरोप है कि कई कालेजों और दूरदराज क्षेत्रों में जागरूकता अभियान पर्याप्त नहीं है। वहीं भाजपा दावा कर रही है कि युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एसआईआर का विवाद केवल मतदाता सूची तक सीमित नहीं है। इसके पीछे

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

मेडिकल कॉलेज नरेंद्रनगर के फिफल्टी में बनाने का प्रस्ताव पारित

नई टिहरी(आरएनएस)। नरेंद्रनगर विधानसभा में फिफल्टी क्षेत्र के ग्रामीणों ने सीएम को भेजे ज्ञापन में मेडिकल कॉलेज फिफल्टी में ही खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत फिफल्टी और पलाम में सिविल सोयम की करीब आठ सौ नाली जमीन मेडिकल कॉलेज के लिए देने का प्रस्ताव भी दे दिया गया है। मखलोगी पट्टी, धारअकरिया, क्वीली, कुंजणी, पालकोट और पौड़ीखाल क्षेत्र के लोगों ने मेडिकल कॉलेज के लिए फिफल्टी का प्रस्ताव पारित किया है।मेडिकल कॉलेज के लिए नरेंद्रनगर विधानसभा के फिफल्टी में जमीन का चयन करने पर क्षेत्र के लोगों ने कॉलेज फिफल्टी में ही खोलने का प्रस्ताव पारित कर सीएम को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने कहा कि 24 जुलाई को उत्तराखंड शासन के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं शिक्षा अनुभाग के द्वारा मेडिकल कॉलेज के लिए टिहरी जिले के फिफल्टी, पलाम और भासौं में जगह का चयन किया गया है।चिकित्सा शिक्षा अनुभाग को फिफल्टी में कॉलेज खोलने की कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। क्षेत्र के लोगों ने कॉलेज के लिए सर्वसम्मत से फिफल्टी का प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने बताया कि कॉलेज बनाने के लिए नैचोली ग्राम पंचायत ने मेडिकल कॉलेज के लिए गांव की सिविल सोयम की छह सौ नाली जमीन देने और पलाम के प्रधान ने भी मेडिकल कॉलेज के लिए गांव में सिविल सोयम की दो सौ नाली जमीन देने का प्रस्ताव दे दिया है।उन्होंने क्षेत्र के दर्जनों गांव के प्रधानों का समर्थन पत्र भेजकर स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल का आभार जताया है।

कांवड़ यात्रा रूट पर आठ एंबुलेंस तैनात, सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी

उत्तरकाशी(आरएनएस)। कांवड़ यात्रा और मानसून के मद्देनजर जिला व पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर गंगोत्री धाम तक पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। वहीं, यात्रा मार्ग पर आठ एंबुलेंस, स्क्रीनिंग केंद्र और चिकित्सा टीमें 24 घंटे तैनात कर दी गई हैं।पुलिस उपाधीक्षक जनक सिंह पंवार ने उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम तक कांवड़ रूट और धाम क्षेत्र का विस्तृत सुरक्षा ऑडिट कर पुलिस व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संवेदनशील स्थलों, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और मानसून के दौरान संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।इस दौरान प्रभारी निरीक्षक हर्षिल प्रदीप तोमर, निरीक्षक अभिसूचना विकास नौटियाल, चौकी प्रभारी गंगोत्री प्रमोद उनियाल, चौकी प्रभारी लंका सुरेंद्र रावत, मंदिर समिति के सदस्य व पुलिस एवं अभिसूचना इकाई के अधिकारी मौजूद रहे।उधर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. श्याम विजय के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्थाएं लागू की हैं। वहीं, गंगोत्री से नगुण तक पूरे यात्रा मार्ग पर आठ एंबुलेंस चिकित्सकीय टीमों के साथ तैनात हैं जो प्राथमिक उपचार, आपात चिकित्सा सहायता और जरूरत पड़ने पर मरीजों को निकटतम स्वास्थ्य संस्थान तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि सभी स्वास्थ्य टीमें 24 घंटे अलर्ट मोड पर कार्य कर रही है।

किमाणा गांव में बढ़ा भूस्खलन का दायरा, दो परिवार किए शिफ्ट

चमोली(आरएनएस)। लगातार हो रही बारिश के कारण ज्योतिर्मठ विकासखंड के किमाणा गांव में भूस्खलन का दायरा बढ़ गया है। रास्तों, खेतों और घरों के आसपास मिट्टी के ढेर लग गए हैं। कटाव से पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। प्रशासन ने खतरे की जद में आए दो परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया है। गांव के अन्य परिवारों में भी दहशत का माहौल बना है। लोगों ने प्रशासन से स्थायी सुरक्षा उपाय करने की मांग की है।गांव के ऊपरी हिस्से में सक्रिय भूस्खलन से बारिश के पानी के साथ बड़ी मात्रा में मलबा और मिट्टी बहकर गांव तक पहुंच रही है। इससे पैदल रास्ते, खेत और घरों के आसपास मिट्टी के ढेर लग गए हैं। कई स्थानों पर रास्तों में कटाव हो गया है जबकि पेयजल लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है। खेतों में खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचा है। ग्राम प्रधान शशि देवी ने बताया कि भूस्खलन का दायरा बढ़ रहा है और गांव में लगातार खतरा बढ़ रहा है। भोग मंडी की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। एसडीएम चंद्रशेखर वशिष्ठ ने बताया कि प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए है। प्रभावित दो परिवारों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। पेयजल लाइन और पैदल मार्गों की मरम्मत के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संभावित विस्थापन की आवश्यकता का आकलन करने के लिए भू-वैज्ञानिक सर्वे भी कराया जाएगा।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

–प्रबंधक विज्ञापन

देवभूमि की 'अदृश्य' अदालत

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड की पहचान केवल हिमालय, चारधाम और प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित नहीं है। यहां का लोकजीवन अपनी समृद्ध लोक परंपराओं, देवी-देवताओं और लोकगाथाओं के कारण भी पूरे देश में अलग स्थान रखता है। इन्हीं लोक मान्यताओं में एक महत्वपूर्ण नाम है ऐड़ी-आछरी का। पहाड़ के गांवों में आज भी जब किसी अनहोनी, रहस्यमयी घटना या जंगल से जुड़े अनुभवों की चर्चा होती है तो ऐड़ी देवता और आछरी का जिक्र स्वत: होने लगता है। कुमाऊं और गढ़वाल के अनेक क्षेत्रों में ऐड़ी देवता को न्याय के देवता और ग्राम रक्षक के रूप में पूजा जाता है। लोकमान्यता है कि ऐड़ी देवता अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अन्याय करने वालों को दंड देते हैं। गांवों में उनके मंदिर और थान आज भी लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र हैं। किसी विवाद या संकट की स्थिति में लोग ऐड़ी देवता के समक्ष मन्नत मांगते हैं और न्याय की गुहार लगाते हैं।

आछरी पहाड़ की लोककथाओं का एक रहस्यमय पात्र है। लोकविश्वास के अनुसार आछरी जंगलों, बुग्यालों और निर्जन स्थानों से जुड़ी अलौकिक शक्ति के रूप में वर्णित होती है। पुराने समय में बुजुर्ग बच्चों और चरवाहों को शाम ढलने के बाद जंगलों में न जाने की सलाह देते थे और इसके लिए आछरी की कहानियां सुनाई जाती थीं। इन कथाओं का उद्देश्य केवल रहस्य पैदा करना नहीं, बल्कि कठिन पहाड़ी परिस्थितियों में लोगों को सतर्क रहने की सीख देना भी था। लोक साहित्य के जानकार मानते हैं कि ऐड़ी-आछरी की कहानियां केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि पहाड़ के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का हिस्सा हैं। इन कथाओं में प्रकृति के प्रति सम्मान, सामुदायिक अनुशासन और लोकजीवन के अनुभव छिपे हुए हैं। जंगलों, नदियों और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों के प्रति सावधानी बरतने का संदेश भी इन्हीं लोककथाओं के माध्यम से पीढ़ी-दर-पीढ़ी पहुंचाया गया।

समय के साथ आधुनिकता ने गांवों की जीवनशैली बदल दी है। मोबाइल और इंटरनेट के दौर में नई पीढ़ी इन लोककथाओं से दूर होती जा रही है। फिर भी कई गांवों में आज भी जागर, लोकगीत और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान ऐड़ी देवता का स्मरण किया जाता है। लोकगायक अपनी प्रस्तुतियों में ऐड़ी देवता की वीरता और न्यायप्रियता का वर्णन करते हैं, जबकि बुजुर्ग आछरी से जुड़ी कहानियों को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सुनाते हैं। सांस्कृतिक विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तराखंड की लोकआस्थाएं केवल धार्मिक विषय नहीं हैं, बल्कि वह समाज के इतिहास, पर्यावरण और लोकमनोविज्ञान को समझने का माध्यम भी हैं। ऐड़ी-आछरी की परंपरा इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार लोकविश्वासों ने पहाड़ के कठिन जीवन में सामाजिक संतुलन और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना को बनाए रखा।

◆जब सरकारी तंत्र से आगे निकल आती है ऐड़ी-आछरी की लोक आस्था
◆ऐड़ी-आछरी पहाड़ों की लोक आस्था, रहस्य व लोकजीवन की जीवंत परंपरा
◆गांवों की चौपाल से जंगलों तक गूंजती हैं ऐड़ी और आछरी की कथाएं
◆आस्था, लोक संस्कृति व प्रकृति से जुड़ी सदियों विरासत आज भी जीवित

आज आवश्यकता इस बात की है कि इन लोककथाओं और परंपराओं का वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से दस्तावेजीकरण किया जाए। इन्हें अंधविश्वास के रूप में खारिज करने के बजाय लोकसंस्कृति की अमूल्य विरासत के रूप में संरक्षित किया जाए। पहाड़ की नई पीढ़ी यदि अपनी जड़ों से जुड़ी रहेगी, तभी ऐड़ी-आछरी जैसी लोकगाथाएं आने वाले समय में भी जीवित रह सकेंगी। ऐड़ी-आछरी केवल एक कथा नहीं, बल्कि उत्तराखंड के पहाड़ों की स्मृतियों, लोकविश्वास, प्रकृति और सांस्कृतिक पहचान का ऐसा अध्याय है, जो आज भी गांवों की हवा, जंगलों की खामोशी और लोकगीतों की धुनों में जीवंत महसूस किया जा सकता है।

उत्तरकाशी की प्राचीन धरोहर होगी सुरक्षित

उत्तरकाशी(आरएनएस)। जनपद में छिपी प्राचीन ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए अब बड़े स्तर पर पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया जाएगा। जनपद के मंदिरों, आश्रमों, संस्कृत महाविद्यालयों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों और निजी संग्रहों में रखी दुर्लभ पाण्डुलिपियों, ताम्रपत्रों और ऐतिहासिक दस्तावेजों की पहचान कर उनका संरक्षण एवं डिजिटलीकरण किया जाएगा।

राष्ट्रीय पाण्डुलिपि सर्वेक्षण अभियान को लेकर जिला स्तरीय समिति की बैठक में इस संबंध में कार्ययोजना तैयार की गई। सीडीओ जय भारत सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले में उपलब्ध पाण्डुलिपियों का व्यापक सर्वेक्षण कर उन्हें अभिलेखीय रूप में सुरक्षित किया जाएगा।सीडीओ ने कहा कि भारत सरकार के ज्ञान भारतम् मिशन के तहत संचालित यह अभियान देश की अमूल्य सांस्कृतिक एवं बौद्धिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण प्रयास है।

स्थानीय जलवायु और संसाधनों के अनुरूप खेती को बढ़ावा देने का वैज्ञानिकों ने दिया सुझाव

नई टिहरी(आरएनएस)। कृषि विज्ञान केंद्र रानीचौरी में आयोजित वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में किसानों की समस्याओं के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया गया। वैज्ञानिकों ने किसानों को अदरक की बेहतर कीमत के लिए सितंबर में कल्ले समेत अदरक की गांठ निकालने, फसलों में एक ही तरह की रासायनिक दवा का लगातार इस्तेमाल न करने और सब्जी फसलों का क्षेत्रफल बढ़ाने का सुझाव दिया।वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार के कुलपति प्रो. भगवती प्रसाद भट्ट की अध्यक्षता में वानिकी महाविद्यालय रानीचौरी के बैठक संपन्न हुई। कुलपति भट्ट ने कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से किए जा रहे कार्यों की सराहना की। विवि के सह निदेशक शोध प्रो. अमोल वशिष्ठ ने कृषि विज्ञान केंद्र में होने वाले कार्यक्रम बताए। कृषि विज्ञान केंद्र रानीचौरी के प्रभारी अधिकारी डॉ. आलोक येवले ने वर्ष 2025-26 की प्रगति और वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना प्रस्तुत की।औद्यानिकी महाविद्यालय भरसार के अधिष्ठाता प्रो. एके जोशी ने किसानों को औद्यानिकी और कृषि फसलों में रासायनिक कीटनाशकों का एक ही समूह लगातार इस्तेमाल करने के बजाय अलग-अलग समूह की दवाओं को बदल-बदलकर इस्तेमाल करने की सलाह दी। निदेशक शैक्षणिक डॉ. अरविंद बिजल्वाण ने किसानों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-अटारी, लुधियाना की प्रधान वैज्ञानिक डॉ. प्रीति ममगाईं ने खाद्यान्न फसलों के प्रदर्शन के लिए कृषि विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर नई तकनीक का प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया। इस मौके पर मुख्य कृषि अधिकारी विजय देवराड़ी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. डीके शर्मा, देवेंद्र सिंह चौहान, सीता चौहान, रीता नेगी, शिवशरण डोभाल, उदय सिंह तड़ियाल, डॉ. कीर्ति कुमारी, डॉ. सचिन कुमार, डॉ. सुमित चौधरी, डॉ. अरुणिमा पालीवाल, डॉ. पंकज कुमार, डॉ. राजेंद्र सिंह बाली आदि मौजूद रहे।

कहीं पसीने की वजह से तो नहीं झड़ रहे हैं आपके बाल ?

गर्मियों में पसीना आना नेचुरल और बहुत ही आम सी बात है। इसे चाह कर भी रोका नहीं जा सकता है क्योंकि पसीना से आपके शरीर का तापमान मेंटेन रहता हैये सेहत के लिए अच्छा होता है लेकिन ज्यादा पसीने आने का असर हमारे चेहरे पर तो पड़ता ही है साथ ही इसका असर बालों पर भी पड़ता है। कई लोगों का कहना है कि गर्मियों में पसीने की वजह से उनका हेयर फॉल ज्यादा होने लगता है। अब सवाल ये है की क्या पसीना सच में हेयर फॉल को बढ़ावा देता है। जानेंगे इस बारे में आगे विस्तार से। विशेषज्ञ कहते हैं कि पसीने में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। जब गर्मियों में पसीना बहता है तो ये पसीना स्कैल्प पर भी बहता है। लंबे समय तक स्कैल्प से पसीना साफ ना किया जाए तो इससे आपके स्कैल्प को नुकसान हो सकता है। लैक्टिक एसिड की वजह से स्कैल्प पर सूजन हो सकती है और बाल कमजोर हो सकते हैं। आपको बता दें कि स्कैल्प में नेचुरल ऑयल होता है जिससे बाल को मजबूती मिलती है लेकिन पसीने से निकलने वाले लैक्टिक एसिड और नेचुरल ऑयल आपस में मिल जाए तो स्कैल्प के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं जिसके कारण स्कैल्प पर ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है कोर्स बंद होने के कारण बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। स्कैल्प पर पसीना रहने से खुजली की समस्या हो सकती है। कई बार ये खुजली इतनी तेज होती है कि आपके नाखून लग जाते हैं। इनमें से खून निकल आता है और स्कैल्प पर दाने हो जाते हैं।इंफेक्शन के कारण बालों के झड़ने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। कई बार पसीना आने के कारण बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है और इसका असर आपके बालों पर भी पड़ता है। इससे हेयर फॉल की समस्या बढ़ सकती है।

कैसे करें बचाव - गर्मी के मौसम में पसीने को रोकना तो संभव नहीं है लेकिन इससे बचने के लिए आप कोशिश करें कि ज्यादा देर तक धूप में ना रहें।अगर आप धूप में निकल भी रहे हैं तो सर को कवर करके निकले। अगर आपके स्कैल्प पर बहुत ज्यादा पसीना है तो इसे टिशू पेपर या किसी सूती कपड़े से अच्छे से साफ करें। गर्मी के दिनों में हफ्ते में दो बार अच्छे से हेयर वॉश करें ताकि इससे आपका सिर्फ साफ रहे। गर्मी के दिनों में भी बालों में ऑयलिंग करें। क्योंकि एक तरफ अगर पसीना आपके नेचुरल ऑयल को नुकसान पहुंचा रहा है तो आप ऑयलिंग करके डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं।इससे हेयर फॉल की समस्या में गिरावट आती है। ध्यान रहे की ऑयलिंग के बाद हेयर वॉश जरूर करें, वरना गंदगी बालों में चिपक जाएगी तो इससे डेंड्रफ की समस्या हो सकती है।और फिर हेयर फॉल हो सकता है।

घर पर बनाएं आइसक्रीम

गर्मियों में आइसक्रीम का सेवन न सिर्फ शरीर को ठंडक देता है, बल्कि इससे ताजगी भी महसूस होती है। हालांकि, बाजार में मिलने वाली आइसक्रीम में आर्टिफिशियल रंग और स्वाद का इस्तेमाल होता है। इस कारण उनका सेवन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। ऐसे में आप घर पर ही ताजा फलों के इस्तेमाल से आइसक्रीम बना सकते हैं, जो स्वाद और स्वास्थ्य दोनों में बेहतरीन हैं। आइए इस तरह की 5 आइसक्रीम की रेसिपी जानते हैं।

तरबूज की आइसक्रीम- सबसे पहले एक ब्लेंडर में कटा हुआ तरबूज, दही, दूध, चीनी, इलायची पाउडर और चुटकी भर नमक डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लें। इसके बाद इस मिश्रण को आइसक्रीम के सांचे में डालकर उसके बीच में एक डंडी लगाएं और फिर इसे करीब 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। जब आइसक्रीम अच्छे से जम जाए तो इसके स्वाद का आनंद लें। आप गर्मियों में तरबूज से बने इन व्यंजनों को भी ट्राई कर सकते हैं।

आम की आइक्रीम- सबसे पहले एक ब्लेंडर में कटे हुए पके आम, दूध, चीनी (स्वादानुसार) और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लें। इसके बाद इस मिश्रण को आइसक्रीम के सांचे में डालकर बीच में एक डंडी लगाएं और फिर इसे 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अगर आपको आइसक्रीम पसंद नहीं है तो घर पर ये 5 मोजितो बनाकर भी पी सकते हैं।

खीरे और पुदीने की आइसक्रीम- इस आइसक्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले एक ब्लेंडर में खीरा (कटा हुआ), नींबू का रस, चीनी और कुछ ताजा पुदीने की पत्तियां डालकर ब्लेंड करें। अब इस मिश्रण को आइसक्रीम के सांचे में डालकर उसके बीच में एक डंडी लगाएं और फिर इसे रातभर के लिए फ्रिज में रख दें। यह आइसक्रीम दोपहर के समय खाने के लिए एकदम परफेक्ट है। इसका स्वाद भी आपको अलग अहसास देगा।

बेरीज आइसक्रीम- ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और ब्लैकबेरी जैसी रसीली और स्वादिष्ट बेरीज पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। ऐसे में इनसे बनी आइसक्रीम का सेवन गर्मियों के लिए बेहतरीन है। सबसे पहले एक ब्लेंडर में ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, नींबू का रस और चीनी डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड करें। अब मिश्रण को आइसक्रीम के सांचे में डालकर उसके बीच में एक डंडी लगाएं और फिर इसे करीब 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। आइसक्रीम के जमने के बाद उसका स्वाद लें।

ब्लूबेरी और नारियल की आइसक्रीम- सबसे पहले एक सॉस पैन में ताजा ब्लूबेरी, मेपल सिरप और पानी डालकर अच्छी तरह से पका लें और फिर इसे ठंडा होने दें। अब नारियल के दूध को बादाम के दूध और मेपल सिरप के साथ मिलाकर फेंटें। इसके बाद आधे आइसक्रीम के सांचे में ब्लूबेरी का मिश्रण डालें और फिर बाकी के आधे में नारियल के दूध वाला मिश्रण डाल दें। अंत में इस सांचे के बीच में डंडी लगाकर इसे रातभर के लिए फ्रीज में रख दें।

'रोटी-बेटी' का रिश्ता और लखपति दीदी का 'सपना'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने रोटी-बेटी के रिश्तों को नई ऊर्जा देने की दिशा में नेपाल के दार्चुला में आयोजित भारत-नेपाल मैत्री बैठक एवं लखपति दीदी सम्मेलन को सीमांत क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य केवल दोनों देशों के पारंपरिक सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना ही नहीं, बल्कि सीमा से लगे क्षेत्रों की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, स्वरोजगार और सामाजिक भागीदारी को भी नई दिशा देना रहा। उत्तराखंड के सीमांत जिलों और नेपाल के दार्चुला क्षेत्र के बीच वर्षों से पारिवारिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। सीमावर्ती गांवों में आज भी दोनों देशों के लोगों के बीच वैवाहिक रिश्ते, सांस्कृतिक मेल-मिलाप और पारंपरिक सहयोग की मजबूत परंपरा देखने को मिलती है। इसी ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक विकास और महिला सशक्तिकरण से जोड़ने का प्रयास इस सम्मेलन के माध्यम से किया गया।

सम्मेलन में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वयं सहायता समूहों की भूमिका, लघु उद्योग, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उद्यम, स्थानीय उत्पादों के विपणन और सीमांत क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसरों पर विशेष चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि यदि सीमा के दोनों ओर महिलाओं को प्रशिक्षण, बाजार और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए तो सीमांत क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सकती है। बैठक के दौरान भारत और नेपाल के बीच सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान को और मजबूत करने, पारंपरिक मेलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा महिला समूहों के बीच नियमित संवाद बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। प्रतिभागियों

❑दार्चुला में भारत-नेपाल मैत्री बैठक व लखपति दीदी सम्मेलन से सीमांत क्षेत्रों को नया संदेश
❑सीमा के दोनों ओर महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण पर जोर
❑भारत-नेपाल के पारंपरिक रिश्तों को विकास और आत्मनिर्भरता से जोड़ने की है यह पहल

ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों की साझा सांस्कृतिक विरासत दोनों देशों की सबसे बड़ी ताकत है, जिसे आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाने की आवश्यकता है।

सीमांत क्षेत्रों का विकास केवल आधारभूत सुविधाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि स्थानीय समाज, महिलाओं और युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना भी उतना ही आवश्यक है। ऐसे सम्मेलन सीमा पार विश्वास, सहयोग और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का माध्यम बन सकते हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी इस आयोजन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत और नेपाल के बीच समय-समय पर सीमा, व्यापार और कूटनीतिक मुद्दों पर चर्चा होती रही है। ऐसे में सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर होने वाले कार्यक्रम दोनों देशों के बीच जन-से-जन संपर्क को मजबूत करने में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। रोटी-बेटी का रिश्ता केवल एक सांस्कृतिक प्रतीक नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच विश्वास और साझी विरासत का आधार माना जाता है।

सम्मेलन में इस बात पर भी बल दिया गया कि सीमांत क्षेत्रों की महिलाएं केवल परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाली सदस्य नहीं हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक नेतृत्व और सांस्कृतिक संरक्षण की प्रमुख धुरी भी हैं। यदि उन्हें शिक्षा, कौशल विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएं तो सीमांत क्षेत्रों में पलायन कम करने और स्थानीय विकास को गति देने में महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। दार्चुला में आयोजित भारत-नेपाल मैत्री बैठक और लखपति दीदी सम्मेलन ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि सदियों पुराने रिश्ते केवल इतिहास की धरोहर नहीं, बल्कि भविष्य के साझा विकास की नींव भी बन सकते हैं। सीमाओं से परे सामाजिक विश्वास, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक साझेदारी का यह प्रयास आने वाले समय में भारत-नेपाल संबंधों को नई मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

रिवर ट्रेजिंग के नाम पर अनियंत्रित खनन रोका जाए

कोटद्वार (आरएनएस)। सिताबपुर निवासी मुजीब नैथानी ने तहसील क्षेत्र की खोह, सुखरो सहित अन्य नदियों में रिवर ट्रेजिंग के नाम पर अनियंत्रित खनन का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है।

पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2020 से नदी किनारों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई रिवर ट्रेजिंग की आड़ में बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है जिससे नदी तट कमजोर हो रहे हैं और बरसात के दौरान कटाव का खतरा लगातार बढ़ रहा है। आरोप लगाया गया है कि निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है।

मुजीब नैथानी ने मांग की कि भविष्य में यदि रिवर ट्रेजिंग का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए तो सबसे पहले नदी किनारे खोदे गए प्रतिबंधित क्षेत्रों की भराई कराई जाए। साथ ही कहा कि उत्तराखंड परिहार नीति का पूर्ण अनुपालन कराते हुए वर्ष 2020 की रिवर ट्रेजिंग की शर्तों से हटाए गए प्रावधानों को दोबारा लागू किया जाना चाहिए।

शब्द सामर्थ्य -006

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं :
1. अनुचित, असत्य, जो ठीक न हो 3. बेवजह, बिनाकारण, व्यर्थ 4. हल्कीनींद, चकमा, धोखा 6. शक्कर पानी आदि का मीठा घोल 10. सोते से उठाना, सावधान करना, प्रदीप्त करना 11. चरमसीमा, सीमांत 14. पानी, आंसू 15. बैठा हुआ, विराजित 16. नृत्य 17. मृतप्राय, मृत्यु के करीब 19. जल, अम्बु 22. उपहार, भेंट 23. खबर, संदेश।

ऊपर से नीचे
1. गणपतिजी, 2. मांगनेवाला, पाने की इच्छा करने वाला 3. मिट्टी के रंग का, मटमैला 5. चला आता हुआ क्रम प्रथा, प्रणाली, रीति-रीवाज, 7. निशाचर, रात में विचरण करने वाला 8. पेड़ का धड़ा जहां से शाखाएं निकलती है, 9. मिठाई, खाने की मीठी चीज 12. शासन, गुप्तबात 13. श्रद्धा, स्त्री, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य 15. विपत्तिग्रस्त, दुखी, अभागा 16. प्रसिद्ध, नामवर 18. स्वप्न, ख्वाब 20. करीब, नज़दीक, समीप 21. सुबह, प्रातः, सबेरा।

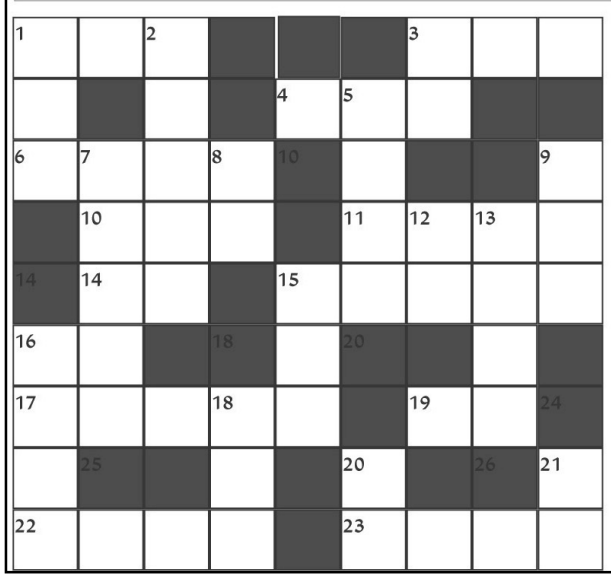

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 05 का हल

अ	भि	षे	क	■	प	स	■	■
जा	त	■	थ	प	थ	पा	ना	■
य	र	का	नी	■	भ्र	■	र	श्मि
ब	घा	र	■	क	ष्ट	प्र	द	■
■	त	ना	त	नी	■	र्व	■	ब
अ	■	मा	■	ज	मा	त	■	ल
स	जा	■	■	■	■	क	ज	रा
बा	■	बे	स	हा	रा	■	ग	म
ब	गु	ला	■	रा	ज	दू	त	■

खाने को पकाने के लिए अपनाएं ये 4 सेहतमंद तरीके

खाना पकाने का तरीका हमारे भोजन के पोषण मूल्य को प्रभावित कर सकता है। कुछ तरीकों से पोषक तत्व बचाए जा सकते हैं, जबकि कुछ से नुकसान भी हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सेहतमंद तरीकों के बारे में बताएंगे, जिनसे आप अपने खाने को ज्यादा पौष्टिक बना सकते हैं और सेहत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। सही खाना पकाने का तरीका अपनाकर आप अपने भोजन का पूरा लाभ उठा सकते हैं।

भाप से खाना पकाना

भाप से खाना पकाना एक बेहतरीन तरीका है, जिससे सब्जियों और अन्य खाने की चीजों के पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। इस विधि में कम से कम पानी का उपयोग किया जाता है, जिससे विटामिन्स और मिनरल्स बचाए जा सकते हैं। भाप से पकाने से सब्जियों का रंग और स्वाद भी बरकरार रहता है। इसके अलावा यह तरीका खाने को अधिक ताजा और पौष्टिक बनाता है, जिससे आपके भोजन का पूरा लाभ उठाया जा सकता है।

उबालकर खाना बनाना

उबालकर खाना बनाना भी एक सेहतमंद तरीका है, खासकर दालों और अनाजों के लिए। इसमें खाने की चीजों को पानी में डालकर धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिससे उनमें मौजूद पोषक तत्व पानी में घुलकर नष्ट नहीं होते। उबालकर खाना बनाने से खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है और यह पौष्टिक बना रहता है। इस विधि से पकाने से खाने का पूरा लाभ उठाया जा सकता है और यह आपके भोजन को अधिक पौष्टिक बनाता है।

ग्रिल करना

ग्रिल करना एक ऐसा तरीका है, जिससे मांसाहारी व्यंजनों को सेहतमंद बनाया जा सकता है। इसमें कम तेल का उपयोग होता है और मांसाहारी व्यंजन ताजगी भरे रहते हैं। ग्रिल करने से मांसाहारी व्यंजनों का स्वाद बढ़ता है और उनमें मौजूद चर्बी कम होती है। इसके अलावा ग्रिल करने से मांसाहारी व्यंजनों में मौजूद पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं, जिससे आपका भोजन अधिक पौष्टिक और सेहतमंद बनता है। यह तरीका आपके खाने को स्वादिष्ट और सेहतमंद बनाता है।

भूनना

भूनना एक ऐसा तरीका है, जिससे सूखे मेवे, मसाले आदि को पकाया जा सकता है। इसमें कम तेल का उपयोग होता है और स्वाद बढ़ता है। भूनने से मसालों का स्वाद और खुशबू उभरकर आती है, जिससे आपका भोजन अधिक स्वादिष्ट बनता है। इसके अलावा भूनने से पोषक तत्व भी सुरक्षित रहते हैं, जिससे आपका भोजन पौष्टिक और सेहतमंद बनता है। यह तरीका आपके खाने को ताजा और पौष्टिक बनाता है।

गर्मियों के दौरान जुखाम या एलर्जी हो गई है? इन 5 तरीकों से पाएं राहत

अगर गर्मियों के दौरान आपको जुखाम या एलर्जी जैसी समस्या हो जाती है तो इसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि इससे आपका संपूर्ण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इसके कारण काम करने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा जुखाम या एलर्जी की समस्या से सिरदर्द, गले में खराश और आंखों में खुजली जैसी कई परेशानियां भी हो सकती हैं। आइए आज हम आपको जुखाम या एलर्जी को ठीक करने के लिए कुछ आसान तरीके बताते हैं।

पानी का सेवन बढ़ाएं - जुखाम या एलर्जी के कारण शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इससे बचने के लिए खुद को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा आप नारियल पानी, ताजे फलों का रस और छाछ आदि भी पी सकते हैं। इससे आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा और जुखाम या एलर्जी की समस्या जल्द ठीक हो जाएगी।

नमक का पानी बनाकर पिएं- जुखाम या एलर्जी के कारण शरीर में नमक की कमी हो सकती है और इससे उभरने के लिए नमक का पानी पीना फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए एक गिलास पानी में थोड़ा-सा नमक मिलाकर इसे पी लें। इससे शरीर में नमक का संतुलन बना रहेगा और जुखाम या एलर्जी की समस्या जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आप नींबू पानी में भी थोड़ा-सा नमक मिला सकते हैं, जिससे स्वाद भी बढ़ जाएगा।

ताजे फलों का सेवन करें- गर्मियों में तरबूज, खरबूज, लीची, आम और अंगूर जैसे कई ताजे फल बाजारों में आसानी से मिल जाते हैं। ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें विटामिन-सी की भरपूर मात्रा होती है। यह पोषक तत्व जुखाम या एलर्जी को ठीक करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा ये फल शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद कर सकते हैं, जिससे ठंड की समस्या का इलाज जल्द होता है। लाभ के लिए इन फलों का सेवन करें।

जुखाम या एलर्जी से बचाव के उपाय- जुखाम या एलर्जी से बचाव के लिए ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन करने से बचें। इसके बजाय हल्का ठंडा खाना खाएं और परेशानी महसूस होने पर ठंडी चीजों का सेवन बिलकुल बंद कर दें। इसके साथ ही ठंड या एलर्जी से ग्रस्त व्यक्ति को ठंडे स्थान पर कम रहना चाहिए और ठंडे पानी से नहाने से बचना चाहिए। इसके अलावा हल्के गर्म पानी या गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। एसी वाले कमरे में सोने से भी परहेज करना चाहिए।

फीमेल एक्टर्स को हल्के में लिया जाता है : कृति सेनन

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन इन दिनों अपनी फिल्म कॉकटेल 2 को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. फिल्म में उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है. अब इस बीच कृति अपने एक इंटरव्यू को लेकर चर्चा में आ गई हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ होने वाले जेंडर बायस पर खुलकर अपनी राय रखी है.

कृति सेनन ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने साथ हुए जेंडर बायस के बारे में बात की है. उन्होंने बताया कि फीमेल एक्टर्स को अक्सर उनके मेल काउंटरपार्ट्स से अलग तरह से जज किया जाता है. कृति ने इंडस्ट्री में काम करने के स्ट्रगल के बारे में बात की और बताया कि असिस्टेंट डायरेक्टर्स अक्सर मेल स्टार्स से डरते हैं, जबकि फीमेल एक्टर्स को अक्सर हल्के में लिया जाता है.

कृति ने बताया कि अगर कोई एक्ट्रेस अपने किरदार या सीन को लेकर सवाल पूछती है तो उसे जरूरत से ज्यादा सवाल करने वाली समझ लिया जाता है, जबकि यही काम कोई मेल स्टार करे तो उसकी तारीफ होती है. एक्ट्रेस ने कहा, जब कोई फीमेल एक्टर सवाल पूछती है, तो ऐसा होता है, कितने सवाल पूछती है ये, अरे 50 सवाल शुरू हो जाएंगे. मुझे लगता है कि इस तरह की बातचीत होती है. इसके उलट, जब कोई मेल स्टार सवाल पूछता है, तो उसे बहुत इन्वॉल्व्ड कहा जाता है. मेरे साथ भी ऐसा हुआ है. जब मैंने वही सवाल पूछे, तो मुझसे कहा गया, इसे ओवरएनालाइज़ मत करो. लेकिन जब ये बात उस लड़के की तरफ से आई, तो उन्होंने कहा, ठीक है, ये किया जा सकता है.

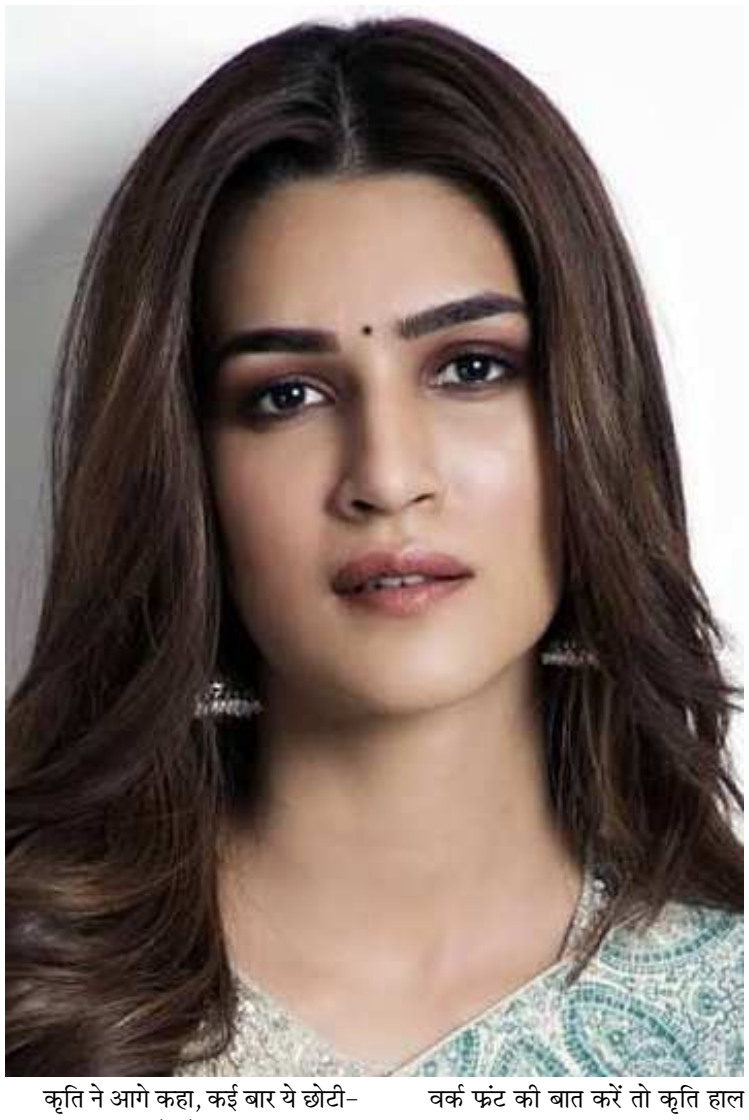

कृति ने आगे कहा, कई बार ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जैसे मेल एक्टर को कैसी कार या कमरा दिया गया और मुझे कैसा कमरा दिया गया. मेरा मतलब है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही मुझे छोटा कमरा या कार मिले, लेकिन इससे मुझे कम महसूस नहीं होता.

वर्क फ्रंट की बात करें तो कृति हाल ही में फिल्म कॉकटेल 2 में नजर आई थीं. इस फिल्म में उनके साथ शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं. होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला.

मानसून के दिनों में दुल्हन जैसी सजीं शनाया कपूर

अभिनेत्री शनाया कपूर ने मानसून के दिनों में सोशल मीडिया पर अपनी बेहतरीन तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में वह दुल्हन जैसी लग रही हैं। तस्वीरों के साथ उन्होंने एक बेहतरीन कैप्शन लिखा है। उनकी तस्वीरों पर उनकी मां समेत कई यूजर्स ने कमेंट किए हैं।

शनाया कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी नई तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि उन्होंने लहंगा और टॉप पहना है। उन्होंने गहने पहने हैं। एक हाथ में भर कर चूड़ियां पहनी हैं। उनकी मांग का टीका उनकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा है।

तस्वीरें शेयर करते हुए अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा बारिश के दिनों में धूप जैसी चमको। शनाया की तस्वीरों पर उनकी मां ने दिल और नजर वाला इमोजी कमेंट किया है, ताकि उन्हें नजर ना लगे। भावना पांडे ने उन्हें खूबसूरत लड़की कहा है। एक और यूजर ने लिखा आप बहुत ही सुंदर हैं।

शनाया कपूर को आखिरी बार फिल्म तू या मैं में देखा गया था। इस फिल्म में उनके साथ आदर्श गौरव थे। बिजॉय नांबियार के निर्देशन में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा नहीं कर सकी थी। शनाया 2025 में विक्रांत मैसी के साथ आंखों की गुस्ताखियां में नजर आ चुकी हैं।

हर की पैड़ी भगवामय, बोल बम के जयकारों से गूंजे घाट

हरिद्वार(आरएनएस)। धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह शिवमय नजर आई। विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी समेत आसपास के सभी प्रमुख गंगा घाट भगवा रंग में रंगे दिखाई दिए। सुबह से ही दूर-दराज के राज्यों से पहुंचे लाखों शिवभक्त कांवड़ियों की भीड़ गंगा तटों पर उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाने के बाद विधि-विधान से गंगाजल भरा और बोल बम, हर-हर महादेव तथा बम-बम भोले के जयकारों के बीच अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। गुरुवार सुबह से हर की पैड़ी, सुभाष घाट, मालवीय घाट और आसपास के घाटों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। कंधों पर सजी आकर्षक और रंग-बिरंगी कांवड़ लिए शिवभक्त पूरे उत्साह के साथ गंगाजल भरते नजर आए। गंगा तटों पर धार्मिक उल्लास और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। घाटों पर हर ओर भगवा वस्त्रधारी कांवड़ियों की मौजूदगी से पूरा क्षेत्र शिवमय वातावरण में डूबा दिखाई दिया। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस, प्रशासन और मेला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। हर की पैड़ी और प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और घाटों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस, एसडीआरएफ, जल पुलिस तथा स्वयंसेवकों की तैनाती रही। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्गों का पालन करने और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का अनुपालन करने की अपील की है।

जनपद में मादक पदार्थों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एनकॉर्ड समिति की बैठक, जागरूकता बढ़ाने के निर्देश

अल्मोड़ा(आरएनएस)। अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय एनकॉर्ड (एनसीओआरडी) समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जनपद में मादक पदार्थों की रोकथाम, तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण, नशामुक्ति और पुनर्वास से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को मानस हेल्पलाइन 1933 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक लोग नशे के खिलाफ अभियान से जुड़ सकें। उन्होंने मादक पदार्थों की गतिविधियों से जुड़े संभावित हॉटस्पॉट का चिह्नीकरण कर वहां नियमित निगरानी और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही नशे की लत से प्रभावित लोगों के उपचार, परामर्श और पुनर्वास के लिए सभी विभागों को समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2026 में जनवरी से जून तक मादक पदार्थों से जुड़े 27 अभियोग दर्ज किए गए, जिनमें 52 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान लगभग 1.33 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि मादक पदार्थों की रोकथाम केवल प्रवर्तन एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज, परिवार, शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न विभागों की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है।

सू- दोकू क्र.006

	1			4			7	
		6	9		2			1
	7			6		8		2
1							8	
	8			5		2		3
3		2			4		1	
	3		2			4		
		8		1	6			7
9			4				2	

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र 05 का हल

3	9	6	8	2	5	4	7	1
8	2	5	1	7	4	6	3	9
7	1	4	6	9	3		2	5
1	8	9	3	6	7	2	5	4
2	6	7	5	4	8	1	9	3
5	4	3	9	1	2	7	8	6
6	7	2	4	3	9	5	1	8
9	5	1	7	8	6	3	4	2
4	3	8	2	5	1	9	6	7

‘साइलेंट’ मोड में चुनावी ‘बिसात’

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भले अभी कुछ समय दूर हों, लेकिन कांग्रेस ने चुनावी तैयारियों का पहिया तेजी से घुमाना शुरू कर दिया है। पार्टी ने अपने बूथ लेवल एजेंटों, विधानसभा प्रभारियों, जिला एवं ब्लाक स्तर के पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में पूरी ताकत के साथ झोंक दिया है। कांग्रेस का दावा है कि यह केवल मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव की बुनियादी तैयारी है। पार्टी के भीतर यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि चुनाव केवल बड़े नेताओं की सभाओं से नहीं, बल्कि बूथ स्तर की मजबूती से जीते जाते हैं। इसी सोच के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बूथवार समीक्षा, मतदाता सूची के सत्यापन, नए मतदाताओं को जोड़ने और छूटे हुए नामों को शामिल कराने का अभियान चलाया जा रहा है।

❑कांग्रेस का बूथ मंथन से बदलेगा उत्तराखंड राज्य का सियासी समीकरण
❑वोटर लिस्ट में मतदाताओं को जोड़ने की होड़ में कौन मारेगा बाजी
❑चेहरों का जमावड़ा नहीं, बूथ की घेराबंदी तय करेगी सत्ता की चाबी
❑कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट, विधानसभा प्रभारी और वरिष्ठ नेता सक्रिय

कांग्रेस संगठन का मानना है कि पिछले चुनावों में बूथ प्रबंधन की कमजोरियों का खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ा था। इस बार पार्टी किसी भी स्तर पर ढिलाई के मूड में नहीं है। विधानसभा प्रभारियों को प्रत्येक बूथ की नियमित निगरानी, स्थानीय कार्यकर्ताओं से संवाद और मतदाता सूची में होने वाले बदलावों पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश नेतृत्व ने सभी जिलाध्यक्षों और विधानसभा प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को केवल औपचारिक प्रक्रिया न समझा जाए। इसे संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान के रूप में चलाया जाए। बूथ एजेंटों से घर-घर संपर्क, नए मतदाताओं का पंजीकरण और मतदाता सूची में त्रुटियों को दूर कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस का यह अभियान सीधे तौर पर चुनावी गणित से जुड़ा हुआ है। मतदाता सूची में छोटी-सी चूक भी चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि पार्टी इस बार बूथ स्तर पर मजबूत नेटवर्क खड़ा करने में जुटी है। दूसरी ओर भाजपा पहले से ही अपने बूथ सशक्तिकरण अभियान को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में कांग्रेस भी संगठनात्मक स्तर पर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। प्रदेश की राजनीति अब केवल जनसभाओं और बड़े नारों तक सीमित नहीं रह गई है। असली मुकाबला बूथ प्रबंधन, मतदाता संपर्क और संगठन की सक्रियता पर टिकता दिखाई दे रहा है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि मतदाता सूची लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि पात्र मतदाता का नाम सूची में नहीं होगा तो लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित होंगे। इसलिए कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि वह प्रत्येक बूथ पर सक्रिय रहकर लोगों की सहायता करें और निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सहयोग दें। कांग्रेस इस अभियान के जरिए दोहरे लक्ष्य पर काम कर रही है। पहला, संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय बनाना और दूसरा, कार्यकर्ताओं में चुनावी ऊर्जा का संचार करना। लंबे समय बाद पार्टी ने बूथ स्तर पर इतनी व्यापक सक्रियता दिखाई है, जिसे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।

अब निगाहें इस बात पर होंगी कि कांग्रेस की यह संगठनात्मक कवायद जमीन पर कितना असर छोड़ती है। उत्तराखंड की राजनीति में जहां भाजपा पहले से मजबूत बूथ नेटवर्क का दावा करती रही है, वहीं कांग्रेस की यह नई सक्रियता आने वाले महीनों में राजनीतिक मुकाबले को और दिलचस्प बना सकती है। चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने-अपने मोर्चे संभालने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान अब केवल निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया नहीं, बल्कि उत्तराखंड की चुनावी राजनीति का नया रणक्षेत्र बनता नजर आ रहा है।

एथनॉल उत्पादन से बढ़ेगी किसानों की आय: सलविंदर कलसी

रुद्रपुर(आरएनएस)। भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के प्रदेश अध्यक्ष सलविंदर सिंह कलसी ने रुद्रपुर सिटी क्लब में आयोजित प्रेसवार्ता में किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में गन्ना, मक्का और चावल जैसी फसलों से एथनॉल उत्पादन की व्यापक संभावनाएं होने के बावजूद किसान इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।उन्होंने राज्य सरकार से एथनॉल उत्पादन के लिए आवश्यक उद्योग और व्यवस्था विकसित करने की मांग की। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष सलविंदर सिंह कलसी ने कहा कि उत्तराखंड एक पर्वतीय एवं ऊर्जा उत्पादन करने वाला प्रदेश है, लेकिन इसके बावजूद यहां किसानों को ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा नहीं मिल रही है।

उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में किसानों को ट्यूबवेल के लिए निशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि उत्तराखंड के किसान इस सुविधा से वंचित हैं। सरकार किसानों के हित में ट्यूबवेल बिजली पूरी तरह निशुल्क करे। सलविंदर सिंह कलसी ने कहा कि राज्य में वर्ग-1, वर्ग-2, नवीन परती एवं अन्य श्रेणी की भूमि पर वर्षों से काबिज किसान खेती कर रहे हैं। जमींदारी प्रथा समाप्त होने के बाद भी ऐसे किसानों को भूमिधरी अधिकार नहीं मिल पाए हैं।

उन्होंने मांग की कि वर्ष 2016 में किए गए नियमितीकरण के समान शुल्क पर सभी प्रकार की काबिज कृषि भूमि का नियमितीकरण कर किसानों को भूमिधरी अधिकार प्रदान किए जाएं। कलसी ने कहा कि यदि प्रदेश में गन्ना, मक्का और चावल आधारित एथनॉल संयंत्र स्थापित किए जाएं तो किसानों की फसलों का बेहतर मूल्य मिलेगा, उनकी आय में वृद्धि होगी और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

पशुचिकित्सा सेवा संघ की अल्मोड़ा जिला कार्यकारिणी गठित

अल्मोड़ा(आरएनएस)। उत्तराखंड राज्य पशुचिकित्सा सेवा संघ, जिला अल्मोड़ा की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए चुनाव मुख्य पशुचिकित्साधिकारी एवं जिला संरक्षक डॉ. योगेश अग्रवाल की उपस्थिति में संपन्न हुए।

चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई, जिसमें सभी पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से चयन किया गया। लगातार दूसरी बार डॉ. जयपाल करगेती, पशु चिकित्साधिकारी धौलादेवी, को अध्यक्ष तथा डॉ. दीपाली लालवानी, वरिष्ठ पशुचिकित्साधिकारी भैंसवाड़ा प्रक्षेत्र, को महासचिव पद पर निर्विरोध निर्वाचित किया गया। नई कार्यकारिणी में डॉ. महेंद्र कुमार मौर्या को उपाध्यक्ष, डॉ. संदीप तिवारी को कोषाध्यक्ष, डॉ. शालिनी पांडे को संयुक्त सचिव, डॉ. पैनी आर्या को मीडिया प्रभारी तथा डॉ. श्वेता यादव को संपर्क अधिकारी चुना गया। चुनाव के बाद सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सदस्यों ने स्वागत करते हुए संगठन को और अधिक मजबूत बनाने की अपेक्षा जताई। निर्वाचन के उपरांत अध्यक्ष डॉ. जयपाल करगेती और महासचिव डॉ. दीपाली लालवानी ने सभी पशुचिकित्साधिकारियों का दोबारा विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संगठन पशुचिकित्साधिकारियों की सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान, उनके अधिकारों की रक्षा तथा विभागीय हितों को लेकर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संघ सभी सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित कर उनकी समस्याओं को संबंधित स्तर तक प्रभावी ढंग से उठाएगा और उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास करेगा। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी डॉ. योगेश अग्रवाल ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एक मजबूत और सक्रिय संगठन कर्मचारियों तथा विभाग दोनों के लिए लाभकारी होता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई कार्यकारिणी पशुचिकित्साधिकारियों के हितों के संरक्षण, उनके सेवा संबंधी मुद्दों के समाधान तथा विभागीय कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में प्रभावी भूमिका निभाएगी। साथ ही उन्होंने सभी सदस्यों से संगठनात्मक एकता बनाए रखते हुए पशुपालकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने और पशुपालन विभाग की योजनाओं को प्रभावी ढंग से जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।

भाजपा विधायक पर मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

हमारे संवाददाता

देहरादून। महानगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने देहरादून के एसपी सिटी को ज्ञापन सौंपकर कर्नाटक के भाजपा विधायक यशपाल सुवर्णा द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एवं उनके परिवार के विरुद्ध की गई कथित आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। इस अवसर पर लालचंद शर्मा ने कहा कि भाजपा विधायक द्वारा राहुल गांधी एवं उनके परिवार के विरुद्ध दिया गया बयान अत्यंत अशोभनीय, अमर्यादित और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की अभद्र और गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने एसपी सिटी से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा यदि प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय कानून के प्रावधानों के अनुसार उचित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। कांग्रेस पार्टी ऐसे कृत्यों का लोकतांत्रिक एवं कानूनीछ तरीके से विरोध जारी रखेगी। इस अवसर पर पूर्व विधायक राजकुमार, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री वीरेंद्र पोखरियाल, दीप बोहरा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता, पार्षद रमेश कुमार मंगू, शाहिद अंसारी, एतात् खान, सिद्धार्थ वर्मा जमाल अहमद आदि कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

ई-20 पेट्रोलः 'आप' ने केंद्र सरकार के फैसले का किया विरोध

देहरादून (सं)। आम आदमी पार्टी, देहरादून ने कहा कि आज देशभर में 7 लाख से अधिक नागरिकों ने ई-20 पेट्रोल नीति के विरोध में आयोजित डिजिटल रैली में भाग लेकर केंद्र सरकार के इस निर्णय के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया। पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद जैन ने कहा कि वर्तमान समय में देश के लगभग 80-90 प्रतिशत नागरिकों के पास वर्ष 2023 से पूर्व निर्मित ऐसे वाहन हैं, जो ई-20 ईंधन के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। ऐसे में ई-20 पेट्रोल को प्रभावी रूप से लागू करना आम जनता पर एकतरफा निर्णय थोपने जैसा है। शरद जैन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लगातार बिना पर्याप्त जनसंवाद के नीतियां लागू कर रही है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों की भावना कमजोर होती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस नीति का प्रारंभ से ही विरोध करती रही है और देशभर के नागरिक भी अपनी आवाज उठा रहे हैं।

जनगणना में भी पहाड़ 'अदृश्य'..

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

अस्थायी रूप से बाहर हैं। कितने गांव पूरी तरह खाली होने की कगार पर हैं। किन क्षेत्रों में रोजगार देकर आबादी लौटाई जा सकती है। किन सीमांत गांवों को विशेष सहायता की आवश्यकता है। लेकिन इसके लिए केवल नारा नहीं, मजबूत कानूनी ढांचा, स्पष्ट प्रक्रिया और विश्वसनीय डेटा संग्रह की व्यवस्था भी चाहिए।

संसद में मुद्दा उठ जाना अच्छी बात है। बहस भी हो जाएगी। समाचार भी बन जाएगा। लेकिन पहाड़ के लोग शायद एक और सवाल पूछेंगे। क्या अगली जनगणना के बाद हमारे गांवों में लोग भी लौटेंगे? क्योंकि उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि गांवों की गिनती कम हो रही है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि गांवों में जिंदगी कम होती जा रही है। यदि जनगणना उस जिंदगी को वापस लाने की दिशा में पहला कदम बनती है, तो यह केवल आंकड़ों का सुधार नहीं होगा, बल्कि पहाड़ के भविष्य का दस्तावेज होगा और यदि यह केवल संसद की बहस बनकर रह गई, तो अगली जनगणना में शायद कुछ और गांव नक्शे पर तो मिलेंगे, लेकिन उनमें रहने वाले लोग नहीं। यही उत्तराखंड की सबसे बड़ी विडंबना है।

'वोटर लिस्ट' पर उत्तराखंड में 'संग्राम'..

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति भी जुड़ी हुई है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा का मुद्दा बनाकर जनता के बीच ले जाना चाहती है, जबकि भाजपा चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर भरोसा जताते हुए विपक्ष के आरोपों को चुनावी राजनीति का हिस्सा बता रही है। यदि यह मुद्दा लगातार गर्माता है तो आने वाले महीनों में यह बेरोजगारी, महंगाई और पलायन जैसे मुद्दों के साथ चुनावी विमर्श का प्रमुख हिस्सा बन सकता है।

अब निगाहें इस बात पर हैं कि चुनाव आयोग कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दों पर क्या प्रतिक्रिया देता है और पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का किस प्रकार निस्तारण करता है। यदि प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध और तथ्यपरक रही तो विवाद स्वतः शांत हो सकता है। लेकिन यदि किसी भी स्तर पर बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम छूटने या हटने की शिकायतें सामने आती हैं, तो यह मामला राजनीतिक से आगे बढ़कर संवैधानिक बहस का विषय भी बन सकता है।

मतदाता सूची लोकतंत्र की बुनियाद है। इसलिए उस पर उठने वाला हर सवाल स्वाभाविक रूप से गंभीर होता है। विपक्ष का अधिकार है कि वह संभावित खामियों की ओर ध्यान दिलाए, वहीं चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक शिकायत की निष्पक्ष जांच कर प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखे। फिलहाल उत्तराखंड में एसआईआर केवल एक प्रशासनिक कवायद नहीं, बल्कि चुनावी राजनीति का नया रणक्षेत्र बन चुका है।

मुख्यमंत्री ने सुनीं जनसमस्याएं, अधिकारियों को त्वरित समाधान के दिए निर्देश

संवाददाता

खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसमस्याएं सुनकर अधिकारियों को त्वरित समाधान करने के निर्देश दिये।

आज यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहियाहेड हेलीपैड स्थित कैंप कार्यालय में जनता एवं जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि जनसेवा ही सरकार का मूल उद्देश्य है और आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का संवेदनशीलता के साथ परीक्षण कर उसका प्रभावी समाधान किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। शासन और प्रशासन की जवाबदेही तभी सार्थक होगी, जब आम नागरिक को उसकी समस्या का शीघ्र एवं संतोषजनक समाधान मिले। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जनहित से जुड़े मामलों में पूर्ण गंभीरता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने को कहा। मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से भी क्षेत्र की विकास संबंधी आवश्यकताओं एवं जनहित के मुद्दों पर चर्चा की तथा आश्वस्त किया कि जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को गति देने और नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है। इसके उपरान्त मुख्यमंत्री द्वारा खटीमा कैंप कार्यालय में 27 दिव्यांगजनों को 77 सहायक उपकरण और 22 वरिष्ठ नागरिकों को 113 सहायक उपकरण, 11 बैटरी रिक्शा, 14 व्हील चेयर, 18 कमोड चेयर, 06 ट्राई साइकिल, 24 हियरिंग मशीन, 40 नी ब्रेस,13 बैशाखी के अतिरिक्त वॉकर, वॉकिंग स्टिक, सिलिकॉन कुशन , सी पी चेयर का वितरण किये गए साथ ही ग्रामोत्थान रीप योजनांतर्गत नारी शक्ति ग्राम संगठन गदरपुर व सत्यमेव जयते सी एल एफ बाजपुर को बोलेरो वाहन तथा एकता सी एल एफ गदरपुर को फूड वैन की चाबी सौंपी। इस अवसर पर दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू,किशन सिंह किन्ना,गंभीर सिंह धामी, रणजीत सिंह नामधारी,मोहिनी पोखरिया, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, वीसी जय किशन, मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी, अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरुद्ध सहित अनेक जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद थे।

कैबिनेट मंत्री जोशी व खजान दास ने किया राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण

संवाददाता

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने डीएवी (पीजी) कॉलेज परिसर में एमडीडीए द्वारा नवनिर्मित 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया।

आज यहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने डीएवी (पीजी) कॉलेज परिसर में एमडीडीए द्वारा नवनिर्मित 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण कर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए देश की एकता, अखंडता एवं गौरव का संदेश दिया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि तिरंगा केवल भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि देश के करोड़ों नागरिकों की आस्था, स्वाभिमान, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रेरणादायी कार्य युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना को और अधिक सशक्त करते हैं तथा उन्हें देश के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में इस प्रकार के राष्ट्रीय प्रतीकों की स्थापना विद्यार्थियों में राष्ट्र के प्रति सम्मान, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का माध्यम बनती है। उन्होंने एमडीडीए एवं कॉलेज प्रशासन को इस सराहनीय पहल के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह ध्वज आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रसेवा और देशभक्ति के लिए प्रेरित करता रहेगा। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने डीएवी (पीजी) कॉलेज परिसर में 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित करने की घोषणा की थी और दिसम्बर 2025 में भूमि पूजन किया गया था। जिसक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा आज लोकार्पण किया गया है। कार्यक्रम से दोनों मंत्रियों ने कॉलेज परिसर स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी तथा उनके अद्वितीय बलिदान को नमन किया।

टिहरी जल समाधि स्मरण दिवसः दीप प्रज्वलित कर पुरानी टिहरी को किया नमन

हमारे संवाददाता

देहरादून। टिहरी जल समाधि स्मरण दिवस के अवसर पर देहरादून के बल्लूपुर क्षेत्र में श्री सुबोध बहुगुणा के निवास पर निर्मित 'पुरानी टिहरी की ऐतिहासिक अनुकृति' में दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर पुरानी टिहरी के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति एवं विरासत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

इस अवसर पर पुरानी टिहरी विस्थापित एवं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अभिनव थापर ने कहा कि 31 जुलाई उत्तराखंड के इतिहास का एक अत्यंत भावुक और स्मरणीय दिवस है। वर्ष 2005 में इसी दिन भागीरथी और भिलंगना नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण पुरानी टिहरी के शेष हिस्से भी जलमग्न होने लगे और अनेक परिवारों को अपना पुश्तैनी घर, बाजार और जीवनभर की स्मृतियाँ छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। टिहरी आज भले ही झील में समा गई हो, लेकिन उसकी सांस्कृतिक विरासत, संघर्ष और गौरव आज भी प्रत्येक उत्तराखंडवासी के हृदय में जीवित है।

राज्य मंत्री विनोद उनियाल ने कहा कि पुरानी टिहरी केवल एक नगर नहीं, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक चेतना, संघर्ष और गौरव का प्रतीक है, जिसकी विरासत को सहेजना हम सभी का दायित्व है। इस अवसर पर सुबोध बहुगुणा द्वारा वर्षों के परिश्रम से तैयार 'पुरानी टिहरी के लैंडस्केप' का अवलोकन किया गया। इस ऐतिहासिक अनुकृति में घंटाघर, राजा का दरबार, आजाद मैदान, टिहरी बाजार तथा गंगा और भागीरथी के प्रवाह मार्ग सहित पुरानी टिहरी की ऐतिहासिक पहचान को सजीव रूप में प्रदर्शित किया गया है। इन प्रतिकृतियों ने उपस्थित लोगों की पुरानी स्मृतियों को पुनः जीवंत कर दिया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री विनोद उनियाल, सुबोध बहुगुणा, कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव थापर, विनोद बहुगुणा, विवेक, शशांक, प्राची, इंदु सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

अपशब्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया बड़ा दिल

कार्यालय संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर से उठी एक घटना ने केवल भारत की राजनीति ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संवाद, राजनीतिक असहमति और सार्वजनिक शिष्टाचार पर भी नई बहस छेड़ दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि प्रदर्शन के दौरान उन्हें और उनकी दिवंगत मां को अपशब्द कहे गए, लेकिन वह संबंधित युवाओं को भटके हुए बच्चे मानते हैं और उन्हें दंडित करने के बजाय मार्गदर्शन देने के पक्षधर हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत में छात्र आंदोलनों, राजनीतिक ध्रुवीकरण और सोशल मीडिया पर बढ़ती तीखी भाषा को लेकर व्यापक चर्चा चल रही है।

लोकतंत्र में सरकार का विरोध नागरिकों का अधिकार है। भारत का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और जंतर-मंतर लंबे समय से लोकतांत्रिक विरोध का प्रतीक माना जाता रहा है। लेकिन इस घटना ने एक मूलभूत प्रश्न खड़ा किया है क्या राजनीतिक असहमति के नाम पर व्यक्तिगत या पारिवारिक अपमान स्वीकार्य है? प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि अपशब्द किसी समस्या का समाधान नहीं हैं और समाज का दायित्व है कि वह भटके हुए युवाओं को सही दिशा दिखाए, न कि केवल दंड की मांग करे। दुनिया के कई लोकतंत्रों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अन्य देशों में भी राजनीतिक ध्रुवीकरण के साथ सार्वजनिक संवाद की भाषा लगातार कठोर हुई है। चुनावी रैलियों, सोशल मीडिया और विरोध प्रदर्शनों में व्यक्तिगत हमले बढ़े हैं।

ऐसे माहौल में यदि कोई शीर्ष निर्वाचित नेता सार्वजनिक रूप से संयम, क्षमा और संवाद की बात करता है, तो वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन सकता है।

◆भटके बच्चों को सजा नहीं, सही दिशा की है जरूरत
◆विरोध के तीखे सुरों के बीच पीएम का वीडियो संदेश

दूसरी ओर, आलोचक यह भी पूछ सकते हैं कि केवल भाषा पर नहीं, बल्कि विरोध प्रदर्शनों से जुड़े अन्य मुद्दों जैसे पुलिस कार्रवाई, छात्रों की शिकायतें और आंदोलन के मूल कारणोंकूपर भी समान गंभीरता से संवाद होना चाहिए।

प्रधानमंत्री का संदेश भावनात्मक भी था और राजनीतिक भी। उन्होंने कहा कि उनकी दिवंगत मां को भी अपशब्द कहे गए, लेकिन इसके बावजूद वे युवाओं को दंडित करने के बजाय उन्हें माफ करना चाहते हैं और समाज से भी यही आग्रह करते हैं। यह संदेश समर्थकों के बीच संयम और नैतिक नेतृत्व के रूप में देखा जा रहा है। वहीं आलोचक यह तर्क दे सकते हैं कि राष्ट्रीय बहस केवल भाषा तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन कारणों पर भी होनी चाहिए जिनसे विरोध प्रदर्शन पैदा हुए।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसलिए यहां की राजनीतिक घटनाएं वैश्विक मीडिया और अंतरराष्ट्रीय नीति विश्लेषकों की नजर में रहती हैं। यह घटना दो समानांतर संदेश देती है लोकतंत्र में विरोध की जगह है। लेकिन लोकतंत्र की गुणवत्ता इस बात से भी तय होती है कि विरोध किस भाषा और मर्यादा के साथ व्यक्त किया जाता है। यदि असहमति संवाद में बदले तो लोकतंत्र मजबूत होता है। यदि वह केवल व्यक्तिगत अपमान में बदल जाए, तो सार्वजनिक विमर्श कमजोर पड़ता है। जंतर-मंतर की यह घटना केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्कृति की परीक्षा भी है। प्रधानमंत्री का क्षमा का संदेश एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्तक्षेप है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि विरोध की मूल शिकायतों पर खुला और संस्थागत संवाद जारी रहे। आखिरकार, किसी भी परिपक्व लोकतंत्र की पहचान केवल इस बात से नहीं होती कि वहां कितनी तेज आवाजें उठती हैं, बल्कि इस बात से होती है कि असहमति को किस गरिमा, संवेदनशीलता और लोकतांत्रिक मर्यादा के साथ सुना और व्यक्त किया जाता है।

कोर्ट के नोटिस के बाद मंत्री को पद से हटाया जाएः पंकज

संवाददाता

देहरादून। कांग्रेस प्रवक्ता व अधिवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री ने कहा कि स्पेशल विजिलेंस कोर्ट से नोटिस के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को जांच पूरी होने तक पद से हटया जाए। आज यहां परेड ग्राउण्ड स्थित प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उनके द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर मांग की है कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के विरूद्ध अपनी घोषित जीरो टॉलरेंस नीति को व्यवहार में सिद्ध करते हुए स्पेशल विजिलेंस कोर्ट द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुडे प्रकरण में नोटिस जारी होने के उपरांत कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को जांच पूर्ण होने तक मंत्री मंडल से पृथक करें। उन्होंने कहा कि विशेष न्यायाधीश सतर्कता अधिष्ठान द्वारा 25 जुलाई को पारित आदेश के तहत मंत्री गणेश जोशी को बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार नोटिस जारी कर तीन सितम्बर को न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने कहा कि न्यायालय की प्रक्रिया का सम्मान करते हुए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना सरकार की संवैधानिक एवं नैतिक जिम्मेदारी है। क्षेत्री ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने से पूर्व दोषी नहीं माना जा सकता है किन्तु लोकतांत्रिक व्यवस्था में नैतिक उत्तरदायित्व और जनविश्वास सर्वोपरि है। यदि सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है तो जांच पूरी होने तक संबंधित मंत्री को पद से अलग कर पूरे प्रदेश में स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि कानून और नैतिकता सत्ता से ऊपर है। पंकज क्षेत्री ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध जनभागीदारी बढाने के उददेश्य से एक हेल्पलाइन नम्बर भी जारी किया। इस अवसर पर प्रवक्ता श्रीमती सुजाता पॉल, आशीष नौटियाल, आशीष सैनी, हिमांशु बहुगुणा भी उपस्थित रहे।

पीएम को अपशब्द कहने वाली लड़की ने माफी मांगी, कहा 'मैं अभी मात्र 15 साल की हूं!'

नई दिल्ली (सं)। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाली लड़की ने माफी मांगी है। उसने कहा कि मैं अपनी बातों के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। अपना वीडियो जारी कर लड़की ने कहा कि वो उसकी पहली और आखिरी गलती थी, वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। उसने कहा, मैं अपने दोस्तों के साथ सीपी गई थी, जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहां कोक पी, वहां बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए थे, जो प्रधानमंत्री जी को गालियां दे रहे थे। मैं भी उन लोगों के बहकावे में आ गई थी और मैंने ये सब बोल दिया। मैं अभी मात्र 15 साल की हूं, मैंने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। मैंने बहुत गंदी बातें बोली हैं। लेकिन ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी, इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। लड़की का यह 15 साल की उम्र का दावा पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा जुटाई गई जानकारियों से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है, जिसने इस केस को और अधिक रहस्यमयी बना दिया है। लड़की ने खुद अपनी उम्र 15 साल बताई है, जबकि नोएडा पुलिस ने कल बताया था कि आरोपी लड़की की उम्र 25 से 28 साल के बीच है। आरोपी लड़की अपनी मां के साथ रहकर पढ़ाई करती है।

खाकी में 'बगावत' या जवानों का 'दर्द'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड पुलिस में अनुशासन और असंतोष को लेकर चल रही बहस ने नया मोड़ ले लिया। छात्र आंदोलन के दौरान दिए गए बयान के बाद निलंबित किए गए कांस्टेबल शेर सिंह के समर्थन में अब एक और पुलिसकर्मी के सामने आ गया है। शेर सिंह प्रकरण पहले ही राज्य की राजनीति और सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ था। अब दूसरे पुलिसकर्मी के सामने आने से यह मामला एक व्यक्तिगत विवाद से आगे बढ़कर संस्थागत चर्चा का विषय बन गया है। पुलिस बल एक अनुशासित सेवा है। सेवा नियमों के अनुसार कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सार्वजनिक मंचों पर ऐसे बयान न दें, जिनसे विभाग की निष्पक्षता या अनुशासन पर प्रश्न उठें। दूसरी ओर, यह मामला इस बहस को भी जन्म देता है कि सरकारी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की सीमा क्या होनी चाहिए और किन परिस्थितियों में विभागीय कार्रवाई उचित मानी जाती है।

◆निलंबित शेर सिंह के पीछे खड़ा हुआ एक और सिपाही
◆छात्र आंदोलन से उठी चिंगारी अब बनने लगी है शोला
◆उत्तराखंड पुलिस के अंदरुनी असंतोष आ गया है सामने

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब राज्य में विभिन्न राजनीतिक और छात्र संगठनों के आंदोलन चर्चा में हैं। विपक्ष इस मामले को कर्मचारियों के असंतोष और सरकार के रवैये से जोड़ सकता है, जबकि सत्तापक्ष का जोर इस बात पर रहेगा कि वर्दीधारी बलों में अनुशासन सर्वोच्च है और सेवा नियमों का पालन अनिवार्य है। पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। एक वर्ग इसे पुलिस कर्मियों के भीतर बढ़ती बेचैनी का संकेत बता रहा है, जबकि दूसरा वर्ग इसे व्यक्तिगत घटनाओं को अनावश्यक रूप से व्यापक रूप देने की कोशिश मान रहा है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि संबंधित पुलिसकर्मी के मामले में विभाग क्या कार्रवाई करता है। यदि विभागीय जांच शुरू होती है, तो यह स्पष्ट होगा कि पुलिस मुख्यालय इस प्रकरण को किस दृष्टिकोण से देख रहा है।

चार लुटेरे गिरफ्तारः 80 हजार की नगदी व तमंचा, कारतूस बरामद

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। भैंस खरीदने गये एक व्यक्ति से तमंचे की नोक पर करीब एक लाख रूपये की नगदी लूटने के मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए चार लुटेरो को गिरफ्तार कर लिया है। जिनके पास से 80 हजार की नगदी व तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। मामले में शामिल एक महिला आरोपी को पुलिस पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

जानकारी के अनुसार बीती 20 जुलाई को इमरान पुत्र अल्लादिया निवासी ग्राम सिहचंदी थाना भगवानपुर हरिद्वार द्वारा कोतवाली लक्सर में तहरीर देकर बताया गया था कि 14 जुलाई को उनके साथ अज्ञात 4 व्यक्तियों द्वारा मारपीट, गाली गलौच, व जान से मारने की धमकी देकर एक लाख रुपयें लूट लिए गये है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी गयी। लूट का खुलासा करने में जुटी पुलिस टीम द्वारा कडी से कड़ी जोड़कर घटना की एक महिला आरोपी को लूटी गयी धनराशि के साथ बीती 28 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया था। जबकि घटना में फरार चल रहे अन्य आरोपी लगातार अपने-अपने घरों से फरार रहकर गिरफ्तारी से बचने के लिये लगातार ठिकाने बदलकर रह रहे थे जो लूटी गयी धनराशी को आपस में बांटकर कही जाने के फिराक में थे। जिन्हे पुलिस ने देर रात मय लूटी गयी धनराशि के साथ लक्सर से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम सुधांशु उर्फ काका पुत्र अवदेश उर्फ बाबूराम निवासी ग्राम अकौढा खुर्द थाना कोतवाली लक्सर जनपद हरिद्वार, वंश पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम कंकरखाता कोतवाली लक्सर जनपद हरिद्वार, अनुज पुत्र मामचंद निवासी ग्राम अकौढा खुर्द थाना कोतवाली लक्सर जनपद हरिद्वार व आकाश पुत्र मेनपाल निवासी ग्राम अकौढा खुर्द थाना कोतवाली लक्सर जनपद हरिद्वार बताये जा रहे है।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकारः
वी के अरोड़ा, *एडवोकेट*
बैजनाथ, *एडवोकेट*

कार्यालयः दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोटः सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्री के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।